लेवी खत्म करने से शुगर फर्मों का प्रॉफिट बढ़ेगा

[सूरज साउकार *मुंबई*]

शुगर सेक्टर पर सरकार ने अपना कंट्रोल कुछ कम किया है। इस सेक्टर की कंपनियों को लॉन्ग टर्म में इससे काफी फायदा होगा। सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है, जब शुगर कंपनियां गन्ने की ज्यादा कीमत से परेशान हैं। वहीं, चीनी के दाम भी फ्लैट हैं। अगर सरकार रंगराजन कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें मान लेती, तो शुगर सेक्टर को कहीं ज्यादा फायदा होता।

ईटीआईजी की एनालिसिस के मुताबिक, सरकार के शुगर सेक्टर पर कंट्रोल कम करने से बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी मिल्स और श्री रेणुका शुगर्स के टैक्स से पहले प्रॉफिट में क्रमशः 130 करोड़, 100 करोड़ और 80 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। डीकंट्रोल के तहत सरकार ने लेवी सिस्टम खत्म कर दिया है। तीनों कंपनियों के टैक्स से पहले प्रॉफिट के बारे में यह अनुमान पिछले साल के प्रोडक्शन के आधार पर लगाया गया है। इस वजह से नीयर टर्म में शुगर कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ सकती है। लेवी सिस्टम के तहत मिलों को अपने प्रोडक्शन का 10 फीसदी हिस्सा 19.1 रुपए किलो के भाव पर सरकार को बेचना पड़ता था। वहीं, मार्केट में चीनी की कीमत 34 रुपए किलो है। इससे मिलों के मुनाफे में सेंध लगती थी। सप्लाई मैकेनिज्म को खत्म करने से भी मिलों को फायदा होगा। हर मिल को अभी मार्केट में तय मात्रा में चीनी बेचनी पड़ती है। इसके खत्म होने से मिलों को प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिल पाएगी। कंपनियां अब ज्यादा चीनी तब बेच पाएंगी, जब उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी।

रंगराजन कमेटी ने रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म का प्रपोजल दिया था। इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत मिलों को चीनी और बायप्रोडक्ट्स का 70 फीसदी रेवेन्यू राज्य सरकारों और किसानों से शेयर करना था। इससे चीनी कंपनियों के प्रॉफिट में ज्यादा उतार-चढ़ाव की मुश्किल खत्म हो जाती। चीनी का दाम कम होने पर उसका बोझ कंपनियां और किसान उठाते।

अक्टूबर 2012 से सितंबर 2013 के करेंट शुगर ईयर में गन्ने की ज्यादा कॉस्ट के चलते मिलों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। इसके अलावा इस साल चीनी का प्रोडक्शन उम्मीद से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इससे चीनी के दाम पर प्रेशर बना हुआ है। 31 मार्च 2013 तक शुगर प्रोडक्शन 2.3 करोड़ टन रहा। इस सीजन के खत्म होने तक प्रोडक्शन 2.4 करोड़ टन पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए शुरुआती अनुमान 2.3 करोड़ टन का लगाया था। इस वजह से चीनी की कीमत अभी 34 रुपए किलो हो गई है, जो दिसंबर 2012 में 37 रुपए किलो थी। हालांकि, आगे चलकर चीनी के दाम में गिरावट आने के आसार नहीं हैं। गन्ने की खेती वाले कई इलाकों में सूखा पड़ा है। इससे अगले सीजन में वहां इसकी पैदावार कम रह सकती है। मौजूदा कीमत पर कई बड़ी शुगर कंपनियों के शेयर बुक वैल्यू के 0.3-0.8 गुना पर मिल रहे हैं।

लेखा-जोखा

शुगर इंडस्ट्री

- **लेवी सिस्टम** के तहत मिलों को अपने प्रोडक्शन का 10 फीसदी हिस्सा 19.1 रुपए किलो के भाव पर सरकार को बेचना पड़ता था
- **मार्केट में** चीनी की कीमत 34 रुपए किलो है, इससे मिलों के मुनाफे में सेंध लगती थी
- **सप्लाई मैकेनिज्म** को खत्म करने से भी शुगर मिलों को फायदा होगा

Economic Times

9/4/13